Written by मेरी बटिया संवाददाता
Tuesday, 10 July 2018 00:56

: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ : □□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ 27 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□ : □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□-□□□□ □□□□ :

□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□ :स्□त्री-खतना की परम्□परा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गहरी चिंता जतायी है□ दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में अबोध लड़कियों के मादा जननांग विघटन की परम्□परा पर सवाल उठाते हु□ सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यह परम्□परा लड़की के शारीरिक "अखंडता" का उल्लंघन करता है□ मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हु□ बताया कि यह अभ्यास लड़की बच्चों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाता है और उन्हें प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है□

□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□

उन्होंने खंडपीठ को बताया, जिसमें जस्टिस □□म खानविलकर और डीवाई चंद्रचुद भी थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और लगभग 27 अफ्रीकी देशों जैसे देशों ने इस अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया है□ मुस्लिम समूह के लि□ उपस्थित वरिष्ठ वकील □□म सिंघवी ने कहा कि मामला संविधान बेंच को संदर्भित किया जाना चाहि□ क्योंकि यह धर्म की आवश्यक अभ्यास के मुद्दे से संबंधित है जिसे जांचने की आवश्यकता है□

खंडपीठ ने कहा, "□क व्यक्ति की शारीरिक अखंडता धर्म और उसके आवश्यक अभ्यास का हिस्सा क्यों होनी चाहि□," इस अभ्यास ने □क लड़की के शरीर के "अखंडता" का उल्लंघन किया□ "किसी और का नियंत्रण क्यों होना चाहि□ □क व्यक्ति की जननांगों पर, "यह कहा□ संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, वेणुगोपाल ने केंद्र के रुख को दोहराया और कहा कि इस अभ्यास ने बालिका के विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया और इसके अलावा, इस तरह के जननांग विघटन के उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है□

□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□ □□□□□□□□-□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□:-

□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□

दूसरी ओर सघिवी ने इस्लाम में पुरुष खतना (खटना) के अभ्यास को संदर्भति किया और कहा कि सभी देशों में इसकी अनुमति है और यह स्वीकार्य धार्मकि अभ्यास है और सुनवाई स्थगति करने की मांग की गई है। खंडपीठ ने अब पीआई। ल तय कर दी है 16 जुलाई को सुनवाई के मुद्दे पर वकील सुनीता तवािरी ने दायर किया। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल और तेलंगाना को पीआई। ल के पक्ष बनाने का आदेश दिया था, जिसने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़कियों की महिला जननांग उत्परिवर्तन के अभ्यास को चुनौती दी है। इसने आदेश दिया कि केरल और तेलंगाना जैसे राज्य, जहां बोहरा मुस्लिम समुदाय रहते है, को मुकदमेबाजी के पक्ष भी बनाया जाना चाहि। और उन्हें भी नोटिस जारी करना चाहि।। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासति प्रदेश दिल्ली के मामले में पहले से ही राज्य है।

अदालत ने 8 मई को दिल्ली स्थति वकील सुनीता तिवारी द्वारा उठा। ग। मुद्दों की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी कि महिला जननांग उत्परिवर्तन का अभ्यास "बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील" था। उसने नोटिस जारी कि। थे और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के अलावा महिला और बाल विकास सहति चार केंद्रीय मंत्रालयों से जवाब मांगा था, जहां शिया मुस्लिम हैं, दाऊदी बोहरा मुख्य रूप से रहते हैं। तिवारी ने अपनी याचिका में केंद्र और राज्यों को देश भर में 'खटना' या "मादा जननांग उत्परिवर्तन" (। फजी। म) के अमानवीय अभ्यास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। "

याचिका ने । फजी। म को । क अपराध बनाने की दिशा मांगी है जिस पर कानून प्रवर्तन । जेंसियां । । स्वयं पर संज्ञान ले सकती हैं। इसने कठोर सजा के प्रावधान के साथ अपराध को "गैर-संगत और गैर-जमानती" बनाने की भी मांग की है। कानून और न्याय मंत्रालय, सामाजकि न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय को याचिका के पक्ष भी दि। ग। है, जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सम्मेलनों को संदर्भति करते हैं, जिन पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है। याचिका में कहा गया है कि मादा जननांग उत्परिवर्तन के अभ्यास के परिणामस्वरूप पीड़ितों के बुनियादी मौलकि अधिकारों के गंभीर उल्लंघन हु। है, जो इन मामलों में नाबालिग हैं। । फजी। म "अवैध रूप से लड़कियों (पांच साल के बीच और युवावस्था प्राप्त करने से पहले) पर" अवैध रूप से "किया जाता है और" बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमकि घोषणा के खिलाफ है, भारत भारत । क हस्ताक्षरकर्ता है ", याचिका ने कहा, इस अभ्यास को "। क लड़की के शरीर के लि। स्थायी रूप से अक्षमता" के कारण जोड़ा गया।

□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

"खटना 'या' । फजी। म 'या' खफ्द 'का अभ्यास लिंगों के बीच असमानता पैदा करने और महिलाओं के प्रति भेदभाव करने के लि। भी है। चूंकि यह नाबालिगों पर किया जाता है, इसलि। यह बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का भी उल्लंघन करता है क्योंकि यहां तक । । कि नाबालिग याचिका में कहा गया है कि व्यक्ति की सुरक्षा, गोपनीयता का अधिकार, शारीरकि अखंडता और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार से स्वतंत्रता का अधिकार है। "यह किसी भी चिकित्सा कारण के बिना दाऊदी बोहरा धार्मकि समुदाय के भीतर हर लड़की के बच्चे पर । क अनुष्ठान किया जाता है और कुरान में कोई संदर्भ नहीं है। यह बच्चे और मानवाधिकारों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह मानवाधिकारों की सार्वभौमकि घोषणा का भी उल्लंघन करता है और 1 99 6 के अवैध आप्रवासन सुधार और आप्रवासी उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में । क अपराध है और अब ऑस्ट्रेलिया और कुछ में अपराध अन्य देशों के साथ ही, "यह दावा किया। भारत में अवैध कानून घोषति करने के लि। । फजी। म या खटना पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानून नहीं है। "

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ :-

Written by मेरी बटियाि संवाददाता
Tuesday, 10 July 2018 00:56

□□□□□